



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 2018/कार्तिक 09, 1940

No. 352]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2018/KARTIKA 09, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2018

प्रकरण सं.-19/2018

(निर्णायक समीक्षा जांच)

विषय – कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा.सं. 7/36/2018- डीजीटीआर.— मै. एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (जिन्हें आगे आवेदक या याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कोरिया गणराज्य और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. यतः याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों की मूल

की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसके जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

क. पृष्ठभूमि

3. यतः चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 की जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। दिनांक 19 जून, 2014 के प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अन्तरिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 25 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं 36/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात, यह पाया गया कि चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से आयात न्यूनतम सीमा से कम थे और तदनुसार उन देशों से आयातों के विरुद्ध जांच को समाप्त कर दिया गया। दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के अंतिम जांच परिणाम (अधिसूचना सं. 14/7/2013-डीजीएडी) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिशों के आधार पर, दिनांक 27 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 23/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

ख. संबद्ध देश

4. इस जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य और थाइलैंड हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) है, जिसमें इसकी किस्में – मध्यम गुणवत्ता टेरेफ्थेलिक एसिड (एमटीए) और गुणवत्तायुक्त टेरेफ्थेलिक एसिड (क्यूटीए) शामिल हैं। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में वर्णित के समान है।

6. विचाराधीन उत्पाद एक सफेद फ्री क्रिस्टलीय पाउडर है। टेरेफ्थेलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र $C_6H_4(COOH)_2$ है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावशाली होता है और जल और अल्कोहल में खराब ढंग से विलेय है।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ कोड 29173600 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. समान वस्तु

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद का दायरे पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचारित के समान ही रहा है। याचिकाकर्ता कंपनियां द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

इ. घरेलू उद्योग

10. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन मै. एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है।

11. उपलब्ध सूचना के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या निर्यातिक या उसके किसी आयातक से संबंधित हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसलिए, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर

याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

च. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

12. यतः प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को ध्यान के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. जांच अवधि

13. वर्तमान जांच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की है और क्षति विश्लेषण में 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 और जांच अवधि शामिल होगी।

ज. प्रक्रिया

14. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं 14/7/2013-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार निदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ज. समय-सीमा

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "या" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ढ. असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2018

Case No. – 19/2018

(Sunset Review Investigation)

Subject: Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation on imports of Purified Terephthalic Acid (PTA), originating in or exported from Korea RP and Thailand

F. No. 7/36/2018-DGTR.— M/s MCPI Private Limited and M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the applicants or petitioners) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid (PTA), (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Korea RP and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. Whereas, the petitioners have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Thailand and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. BACKGROUND

3. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, European Union, Korea RP and Thailand was initiated by the Authority vide Initiation Notification dated 8th October, 2013. Vide preliminary findings dated 19th June, 2014, the Designated Authority recommended imposition of provisional duty, which was imposed vide Notification No. 36/2014 – Customs (ADD) dated 25th July, 2014. Thereafter, it was found that the imports from China PR and European Union were below de minimis and accordingly investigation as against imports therefrom were terminated. Vide final findings [Notification No.14/7/2013-DGAD] dated 7th April, 2015, the Designated Authority recommended imposition of duty against imports of subject goods from Korea RP and Thailand. On the basis of the said recommendations, anti-dumping duty was imposed Notification No. 23/2015 – Customs (ADD) dated 27th May, 2015.

B. SUBJECT COUNTRIES

4. The countries involved in this investigation are Korea RP and Thailand.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The product under consideration is “Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA)”. The present investigation being a sunset review, the scope of product under consideration is the same as that in the original investigation.

6. The product under consideration is a white free flowing crystalline powder. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is $C_6H_4(COOH)_2$. It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohol.

7. The product under consideration is classified customs tariff code 2917 36 00. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. LIKE ARTICLE

8. The petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

9. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as 'like article' to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY

10. The application for the sunset review has been filed by M/s MCPI Private Limited and M/s Reliance Industries Limited.

11. As per the information available, the petitioners have neither imported the subject goods nor are related to any producer or exporter of subject goods in the subject countries, nor to any importer of the subject goods. Further, the petitioners account for a major proportion in Indian production of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the petitioners as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

F. INITIATION OF SUNSET REVIEW

12. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

G. PERIOD OF INVESTIGATION

13. The Period of Investigation (POI) for the present investigation is financial year 1st April, 2017 to 31st March, 2018 and the injury analysis shall cover the years 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

H. PROCEDURE

14. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/7/2013-DGAD dated 7th April, 2015.

15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

J. TIME LIMIT

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-Dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as nonconfidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

M. NON-COOPERATION

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority